

इस विधेयक का टेक्स्ट पृष्ठ 147 और राज्य सचिव की वेबसाइट voterguide.sos.ca.gov पर देखा जा सकता है।

- ऐसे किन्हीं भी नए राज्य टैक्सों को प्रतिबंधित करता है जिसके राजस्वों को 1979 में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित राज्य की खर्च सीमा से बाहर रखा गया है।
- राज्यव्यापी विशेष टैक्सों के लिए, (1) किसी मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित विशेष टैक्स से निधिकरण प्राप्त करने वाले प्रोग्रामों का चुनाव से पहले लेखा-परीक्षण, और (2) 1 जनवरी, 2026 के बाद अधिनियमित विशेष टैक्सों द्वारा वित्तपोषित प्रोग्रामों के आवर्ती लेखा-परीक्षण को आवश्यक बनाता है।
- यह बताता है कि उसी मतपत्र पर दिखाई देने वाले अन्य मतदाता-अनुमोदित विधेयक अमान्य हैं यदि वे इस विधेयक का के विरोध में हैं और इस विधेयक को अधिक सकारात्मक वोट प्राप्त होते हैं।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- अज्ञात शुद्ध राजकोषीय प्रभाव। विशेष टैक्सों द्वारा वित्तपोषित प्रोग्रामों की नए एक-बारगी और निरंतर लेखा-परीक्षण की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए California राज्य ऑडिटर के लिए बढ़ी हुई लागतें। इन लागतों का भुगतान अधिकतर विशेष टैक्सों से एकत्र किए गये नए राजस्वों से किया जाएगा। लेखा-परीक्षणों से प्राप्त हुई सफ़ािशों को लागू करने से जुड़ी संभावित बचतें।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

परिप्रेक्ष्य

चुनावों का प्रशासन। राज्य सचिव पूरे राज्य में चुनावों की देखरेख करते हैं और राज्य की मतदाता सूचना गाइड (VIG) तैयार करके डाक से भेजते हैं।

मतदाता पहल प्रक्रिया। California के नागरिक राज्यव्यापी पहल प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के कानूनों और संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं। किसी पहल के समर्थक अपनी पहल को मतपत्र के लिए योग्य बनाने हेतु पंजीकृत मतदाताओं से हस्ताक्षर एकत्र करते हैं। राज्य का कानून यह निर्धारित करता है कि समर्थकों को अपनी पहल को मतपत्र के लिए योग्य बनाने हेतु कितने वैध हस्ताक्षर एकत्र करने होंगे। आवश्यक हस्ताक्षरों में से 25 प्रतिशत एकत्र कर लेने के बाद समर्थक राज्य सचिव को सूचित करते हैं।

विशेष टैक्स। राज्य के टैक्सों को विधानमंडल या मतदाताओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जब कोई “विशेष टैक्स” बनाया जाता है, तो उस टैक्स से प्राप्त राजस्व किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रोग्राम के लिए निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ ईंधन टैक्सों का उपयोग केवल सार्वजनिक सड़कों और अन्य परिवहन प्रोग्रामों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

California राज्य लेखा-परीक्षक कार्यालय (राज्य लेखा-परीक्षक)। राज्य लेखा-परीक्षक राज्य सरकार का एक स्वतंत्र और निर्दलीय कार्यालय है। यह समीक्षा करता है कि राज्य और स्थानीय सरकारें कानून का कितनी अच्छी तरह पालन करती हैं, धन का उपयोग कैसे करती हैं और अपने प्रोग्रामों का संचालन कैसे करती हैं। इन समीक्षाओं को लेखा-परीक्षण कहा जाता है। किसी लेखा-परीक्षण में सरकारी कामकाज और कार्यकुशलता में सुधार करने में मदद के

लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। कुछ लेखा-परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य केवल एक बार किए जाते हैं।

प्रस्थापना

मतदाता पहल प्रक्रिया के माध्यम से विशेष टैक्सों के मतपत्र पर आने से पहले एक बार लेखा-परीक्षण कराना आवश्यक बनाता है।

प्रस्ताव 41 के तहत राज्य लेखा-परीक्षक के लिए ऐसे प्रत्येक प्रोग्राम की समीक्षा करना आवश्यक है, जिसे मतदाता पहल प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावित किसी नए या बढ़ाए गए विशेष टैक्स से धनराशि प्राप्त होगी। यह लेखा-परीक्षण तब किया जाएगा जब समर्थक किसी विधेयक को मतपत्र के लिए योग्य बनाने हेतु आवश्यक हस्ताक्षरों में से 25 प्रतिशत एकत्र कर लेंगे, यह उस समय से पहले होगा जब यह पता चलेगा कि पहल मतपत्र के लिए योग्य होगी या नहीं। प्रस्ताव 41 यह निर्धारित करता है कि राज्य लेखा-परीक्षक इन लेखा-परीक्षण में किन बातों को शामिल करेगा, जिनमें लेखा-परीक्षण किए गए प्रोग्राम की वार्षिक लागत को 10 प्रतिशत कम करने के तरीकों की पहचान करना भी शामिल है। प्रस्ताव 41 के तहत राज्य लेखा-परीक्षक के लिए प्रत्येक लेखा-परीक्षण का सारांश तैयार करना आवश्यक है। यदि विशेष टैक्स वाली कोई प्रस्तावित मतदाता पहल मतपत्र के लिए योग्य हो जाती है, तो प्रस्ताव 41 के तहत राज्य लेखा-परीक्षक का सारांश VIG में शामिल करना आवश्यक है। यदि मतदाता विशेष टैक्स को मंजूरी देते हैं, तो एक बार किए जाने वाले लेखा-परीक्षण की लागत नए टैक्स राजस्वों से चुकाई जाएगी।

नए या बढ़ाए गए विशेष टैक्सों से धनराशि प्राप्त करने वाले प्रोग्रामों के नियमित लेखा-परीक्षण। प्रस्ताव 41 के तहत राज्य लेखा-परीक्षक के लिए उन प्रोग्रामों की समय-समय पर समीक्षा करना

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी है

अन्य प्रस्तावों के साथ संभावित परस्पर क्रियाएँ

यदि इसी मतपत्र पर प्रस्ताव 41 को प्रस्ताव 40 की तुलना में अधिक “हाँ” के मत मिलते हैं, तो प्रस्ताव 40 को कानून बनने से रोका जा सकता है, भले ही उसे अधिकांश मतदाताओं के हाँ मत प्राप्त हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालतें यह निर्धारित कर सकती हैं कि प्रस्ताव 41, प्रस्ताव 40 के साथ टकराव में है।

भी आवश्यक है, जिन्हें 1 जनवरी, 2026 के बाद विधानमंडल या मतदाताओं द्वारा बनाए गए या बढ़ाए गए विशेष टैक्सों से वित्तपोषण प्राप्त होता है। ये नियमित लेखा-परीक्षण हर चार वर्ष में किए जाएंगे। प्रस्ताव 41 यह निर्धारित करता है कि राज्य लेखा-परीक्षक इन लेखा-परीक्षण में किन बातों को शामिल करेगा, जिनमें प्रोग्राम की कार्यकुशलता में सुधार के लिए सुझाव भी शामिल हैं। प्रस्ताव 41 यह निर्धारित करता है कि इस नियमित कार्य की लागत का भुगतान नए टैक्स राजस्व से किया जाएगा।

राज्य विनियोजन सीमा। राज्य का संविधान इस बात को सीमित करता है कि राज्य टैक्स राजस्वों के कितने हिस्से को खर्च कर सकता है। यह सीमा सामान्य कोष के टैक्सों और विशेष टैक्सों, दोनों पर लागू होती है। हालाँकि, कुछ प्रकार के खर्च, उदाहरण के लिए बुनियादी ढाँचे पर होने वाले खर्च, इस सीमा से बाहर रखे जाते हैं। प्रस्ताव 41 के तहत राज्य नए विशेष टैक्स से होने वाले खर्च को इस सीमा से बाहर रखने में सक्षम नहीं हो सकता है।

राजकोषीय प्रभाव

राज्य लेखा-परीक्षक की लागत में वृद्धि, जिसका अधिकांश भुगतान नए राजस्वों से किया जाएगा। प्रस्ताव 41 नई और नियमित लेखा-परीक्षण आवश्यकताएँ बनाकर राज्य लेखा-परीक्षक की लागतों को बढ़ाएगा। ये लागतें (1) प्रस्तावित और मंजूर किए गए नए या बढ़ाए गए विशेष टैक्सों की संख्या और (2) लेखा-परीक्षण किए जा रहे प्रोग्रामों की जटिलता पर निर्भर करेंगी। ये लागतें संभवतः प्रति वर्ष कुछ मिलियन डॉलर के दायरे में होंगी, लेकिन समय के साथ बढ़ेंगी। मतदाताओं या विधानमंडल द्वारा मंजूर किए गए विशेष टैक्सों से संबंधित एक बार किए जाने वाले और नियमित लेखा-परीक्षण की लागतों का भुगतान विशेष टैक्सों से एकल किए गए राजस्व से किया जाएगा। जो विशेष टैक्स अंततः मतपत्र पर नहीं आते हैं या जिन्हें मतदाता अस्वीकार कर देते हैं, उनसे संबंधित एक बार किए जाने वाले लेखा-परीक्षण की लागतों का भुगतान राज्य के सामान्य कोष से

किया जाएगा। (सामान्य कोष वह खाता है जिसका इस्तेमाल राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जेलों सहित अधिकांश सार्वजनिक सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है।)

VIG की छपाई और डाक से भेजने की लागतों में वृद्धि। जब किसी विशेष टैक्स वाली मतदाता पहल मतपत्र पर आती है, तो प्रस्ताव 41 के तहत राज्य लेखा-परीक्षक की समीक्षा का सारांश VIG में शामिल करना आवश्यक होगा। इन लेखा-परीक्षण सारांशों से VIG में कई पृष्ठ जुड़ सकते हैं, जिससे प्रत्येक योग्य पहल के लिए राज्य की छपाई और डाक से भेजने की लागत में कुछ लाख डॉलर की वृद्धि होगी।

यदि राज्य लेखा-परीक्षक की सिफारिशें लागू की जाती हैं तो संभावित बचतें। प्रस्ताव 41 के तहत राज्य लेखा-परीक्षक के लिए प्रोग्रामों की लागत कम करने या उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु सिफारिशें देना आवश्यक है। यदि नीति निर्माता राज्य लेखा-परीक्षक की सिफारिशों को लागू करते हैं और वे सिफारिशें प्रभावी साबित होती हैं, तो प्रस्ताव 41 से बचतें हो सकती हैं या सेवाओं में सुधार हो सकता है। इससे होने वाली कोई भी बचतें भविष्य के निर्णयों पर निर्भर करेंगी और फिलहाल ज्ञात नहीं है।

शुद्ध प्रभाव ज्ञात नहीं है। प्रस्ताव 41 का शुद्ध राजकोषीय प्रभाव अज्ञात है, क्योंकि यह मतदाताओं, विधानमंडल और अन्य नीति निर्माताओं द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करता है।

मुख्य रूप से इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों की सूची के लिए sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2026-ballot-measure-contribution-totals पर जाएँ।

समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html पर जाएँ।